UGC APPROVED JOURNAL - 47746

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 02 | January – March 2018

भारत में बैंकिंग विकास एवं बैंक की प्रवृतियां : एक विवेचना

डॉ० ओम प्रकाश साहु

व्याख्याता

श्रम एवं समाज कल्याण विभाग,

सीता राम साहु कॉलेज, नवादा. बिहार |

सार

आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है मानव शरीर में रक्त नलिका ओं का कार्य रक्त के बहाव को बनाए रखना है। इसी प्रकार बैंक देश के आर्थिक शरीर में मुद्रा एवं शाखा की पूर्ति बनाए रखती है। बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार से सहायता करती है। भारत जैसे विकासशील देश में तो बैंक की भारी महत्व जनता की बचते ही एकत्रित नहीं करती बल्कि इन बचतों को उत्पादक एवं विकास का समान कार्य में लगाती है तथा आवश्यक शाखा की शुद्धिपूर्ति करती है

मुख्य शब्द :अर्थव्यवस्था, भारत , बैंकिंग ,विकास, व्यापारिक इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत में बैंकिंग विकास एवं वर्तमान स्थिति भारत के प्राचीन करण इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली बहुत लंबे काल से चली आ रही है। चाणक्य अर्थशास्त्रओं में इस बात का उल्लेख है कि उस समय महाजन जनता के धन को जमा कराते एवं उधर देते थे। इस बैंकिंग प्रणाली को हम देसी बैंकिंग प्रणाली कहते हैं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में यह प्रणाली टूटने लगी थी। अंग्रेजों ने अपना काम चलाने के लिए एजेंसीग्रहों की स्थापना की। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का इतिहास इन्ही एजेंसी की स्थापना से प्रारंभ होता है।यह ग्रह् अंग्रेजों के कारोबार के साथ-साथ भारतीय जनता का धन भी जमा करती थी एवं उन्हें व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऋण देते थे।

1813 में भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाने से इन एजेंसी ग्रह को भारी धक्का लगा और इनका अर्थ प्रारंभ हो गया। अतः कुछ एजेंसी एजेंसी ग्रह ने मिलकर बैंकों की स्थापना करना प्रारंभ किया परंतु उनकी सफलता नहीं मिली।

भारत में 1906 ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के अनुसार बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से पहली आधुनिक बैंक स्थापित हुई। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। यह तीनों बैंक प्रेसिडेंसी के बैंक के नाम से प्रसिद्ध हुए इनका कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था । बाद में इन बैंकों को नोट निर्माण का अधिकार भी दिया गया था लेकिन इसकी 1862 में वापस ले लिया गया। इन तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई।

1860 के पश्चात भारत में बैंकों का विकास बहुत ही तेज गति से हुआ अत: 1913 में बैंकों की संख्या 560 हो गई लेकिन प्रथम विश्व युद्ध काल में भारतीय बैंक संकट में फस गई जिसके पल्सर 1913 तथा 1924 के बीच 161 फेल हो गए । बैंकों के फेल होने के कारण निम्न थे:-

1. **योग्य बैंक संचालकों का अभाव:** देश में स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित मिलने से भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंकों की संख्या बढ़ गयी लेकिन बैंक के पास योग्य एवं अनुभवी संचालकों का अभाव था। वे बैंकिंग सिद्धांतों एवं व्यापार से अनभिव थे।
2. **जमा पर उचित ब्याज दर :** बैंकों के पास पूंजी का अभाव रहता था अतः वे कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए धन जमा करने वालों को उचित दर से ब्याज देते थे जिसका परिणाम यह होता था कि ऋण लेने एवं देने की ब्याज दरों में बहुत ही कम अंतर होता था।
3. **संचालकों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए बैंक साधनों का दूसरा योग**: कुछ बैंकों के संचालकों द्वारा बैंक के धन को अपने निजी उद्योग में लेना प्रारंभ कर दिया गया जिससे संकट काल में बैंक फेल हो गई।
4. **केंद्रीय बैंकों का अभाव:** भारत में केंद्रीय बैंक 1935 में स्थापित की गई इससे पूर्व यहां पर कोई केंद्रीय बैंक नहीं था जो बैंक को दिशा निर्देश दे सके अतः निर्देशों के अभाव में बैंक फेल हो गई।
5. **नगद कोषों में कमी:** बैंकों के द्वारा ब्याज कमाने के लालच से नगद कोष कम मात्रा में रखे जाते थे अतः जब कभी भी ग्राहक ब्याज अधिक धन निकालने के लिए चेक प्रस्तुत किए जाते तो बैंक को कोषों की कमी के कारण उनसे चेकों का भुगतान करने में असमर्थ रहते इसी प्रकार वह फेल हो जाते थे।
6. **कोषों सट्टेबाजी की क्रियाओं में विनियोग:** बैंकों के संचालकों द्वारा अपने-अपने बैंकों का अधिकार धन सट्टेबाजी की क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता था जिससे बैंकों को भारी हानि उठानी पड़ती थी।

इसी बीच 1920 में तीनों बैंकों को मिलाकर कंपनी निय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही आर्थिक मंदी आ जाने के कारण बैंक पुन : संकट में फंस गई 1929 व 1936 के बीच 481 बैंक फेल हो गए 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति की नियुक्ति की गई जिसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की अत: 1835 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में की गई।

भारत में बैंकिंग संरचना

भारत में बैंकिंग संरचना या व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है

- देसी या असंगठित वर्ग
- आधुनिक या संगठित वर्ग

1. **देसी या असंगठित वर्ग:** इस वर्ग को देसी बेकर के नाम से भी पुकारा जाता है इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो देश में रुपए के लेनदेन का कार्य करती हैं तथा जी ने साहूकार महाजन से आदि के नाम से पुकारा जाता है इस प्रकार के व्यक्ति स्थान स्थान पर पाए जाते हैं जिनका विस्तृत विवरण कृषि वित्त वाले अध्ययन में दिया गया है।
2. **आधुनिक या संगठित वर्ग:** इस वर्ग में वे संस्थाएं आती है जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है यह संस्थाएं इस प्रकार हैं
   - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट
   - बैंक ऑफ इंडिया

- अन्य व्यापारिक बैंक
- सरकारी बैंक
- वशिष्ठ वित्तीय संस्थाएं
- विदेशी विनिमय बैंक

व्यापारिक बैंक की प्रवृतियां

वर्तमान में भारतीय व्यापारिक बैंकों की प्रवृतियां निम्न प्रकार है

1. **शाखाओं का विस्तार:** द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ में भारत में कुल 725 बैंक थे जिनकी 1471 शाखाएं थी लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1955 में इंपीरियल बैंक एवं 1969 में 14 अनुसूचित बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से इनकी शाखा में तेज गति से विकास हुआ है 30 जून 1969 को स्टेट बैंक 14 राष्ट्रीय बैंक व अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या 8262 जो 30 जून 1982 को बढकर 391 77 हो गई है।
2. **बैंक शाखा का विस्तार**: पिछले कुछ वर्ष में बैंक शाखा का विस्तार तेजी से हुआ है बैंकों का 31 मार्च को 1971 को 47 56 करोड़ रुपय बकाया था जो 14 जनवरी 1983 को बढकर 33 01 हो गया है। इस बात को स्पष्ट करता है कि बैंक शाखा का तेजी से विस्तार हो रहा है।
3. **प्राथमिक क्षेत्रों को लोन :** भारतीय बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू होने से बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्रों को लोन देना ही प्रारंभ नहीं कर दिया है बल्कि देने की शर्तें भी आसान कर दी है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, दुर्बल व्यक्ति, जैसे रिक्शा चालक, तांगा चालक टेंपो चालक, छोटे व्यापारी व आदि आते हैं जून 1969 के अंत में सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए लोनों में प्राथमिक क्षेत्रों के दिनों का भाग 22. 3 प्रतिशत था जो 31 मार्च 1982 में बढ़कर 37.7% हो गया है लेकिन अब इस को बढ़ाकर 40% तक किया जा रहा है।
4. **बैंक जमाव का बीमा:** बैंकों के फेल होने की स्थिति में बैंकों में धन जमा कराने वालों के हितों को बचाने की दृष्टि से 1 जनवरी 1962 से बीमा निगम की स्थापना की गई है जो बैंक फेल होने की स्थिति में एक सीमा तक जमाकर्ताओ कि रकमों की क्षति पूर्ति करने की उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। प्रारंभ में यह रकम ₹1500 थी लेकिन बाद में इस को बढ़ाकर 5000, 10000 ₹, 20000 और एक जुलाई 1980 से ₹30000 कर दिया गया है। इस प्रकार यदि कोई बैंक आज फेल होती है तो जमाकर्ता कि बैंक में ₹30000 तक जमा रकम सुरक्षित है।
5. **लीड बैंक योजना:** रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एस० एफ० समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी जिलों को बांट दिया जाए तथा प्रत्येक बैंक के हिस्से में आए जिले में शाखा विस्तार शाखा वितरण एवं सामान्य बैंकिंग विकास का उत्तरदायित्व उस बैंक को सौंप दिया जाए। रिजर्व बैंक ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इस योजना को लीड बैंक योजना का नाम दिया गया रिजर्व बैंक ने देश के 335जिलों को 17 बैंकों में बांट दिया जिसके अनुसार स्टेट बैंक समूह को 89 सेंट्रल बैंक को 33, बैंक ऑफ इंडिया को 30, पंजाब नेशनल बैंक को 28 मिले है।
6. **व्यक्तिगत ऋण योजना:** भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति में एक विशेष बात यह है कि प्राय सभी बैंकों ने व्यक्तिगत ऋण योजनाएं प्रारंभ कर दी है जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कार, स्कूटर, टेलीविजन, रेडियो, सिलाई मशीन आदि के लिए बैंक से ऋण ले सकता है जिसका भुगतान

वह अपनी सुविधाजनक किस्तों में कर सकता है इससे जनता को अपना सर उठाने में सहायता मिलती है।

7. **बैंकों का विनी करण:** पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि छोटे-छोटे एवं आर्थिक बैंकों का विलय बड़े बैंकों में होने लगा है उदाहरण के लिए नारंग बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1 अगस्त में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है।
8. **पारिवारिक प्रतियोगिता में कमी:** व्यापारिक बैंकों को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता होती रहती है लेकिन रिजर्व बैंक बैंक के हस्तक्षेप से इसमें अब कमी आ गई है और लगभग सभी बैंकों की ब्याज दर सम्मान हो गई है।
9. **रिजर्व बैंक का अधिक नियंत्रण :**रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम व बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण एवं नियमन करने से अधिकार मिल गए हैं जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक का इन बैंकों के असर अधिक नियंत्रण हो गया है और उन्हें रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करना पड़ता है
10. **तरल कोष एवं अनुपात :**162 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन कर अनुचित अनुसूचित बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत नगद को स्वयं अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें पहले यह प्रतिशत 25 था जिसे बढ़ाकर 37% कर दिया है। बैंक चाहे तो इससे अधिक तरल कोर्स अनुपात रख सकती है

उपसहंर

स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व देश के बेंकिंग क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह से पूँजीवादी था तथा व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं हितों की पूर्ति करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात व्यापारिक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं आया तथा सामाजिक बैंकिंग की दिशा में व्यापारिक बैंकों ने उदासीन रवैया जारी रखा तो अंतत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बेंकिग क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे बैंकों की कार्यप्रणली तथा ऋण नीतियों में भारी परिवर्तन हुआ बैंकिंग बहुत लंबे समय से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और हाल के दिनों में, प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्रांति आई है। अब हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ विभिन्न बैंकिंग सुविधाएँ बस एक क्लिक की दूरी पर हैं, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास बहुत से चरण से गुजरा हुआ है और तब से लगातार विकसित हो रहा है। भारतीय आबादी का अधिकांश भाग अपनी लेन-देन संबंधी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए बैंकों पर निर्भर है। बैंकिंग है और हमेशा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1] सविता, जी0 (2013), द रोल ऑफ एफ.डी.आई. इन इण्डियन बैंकिंग सेक्टर : वाइज एनालिसिस, ए.एस.एम.एस इण्टरनेशनल ई-जर्नल ऑफ आनगोइंग रिसर्च इन मैनेजमेंट एण्ड आई0टी0.

[2] एगोसिन, एम0 एण्ड आर0 मेयर (2000), फारेन इनवेस्टमेंट इन डेवलपिंग कन्ट्रीज : डज इट क्राउड इन डोमिस्टिक इनवेस्टमेंट, डिस्कशन पेपर नं0 146, अंकटाड, जिनेवा.

[3] फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट पालिसी-2010, डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया.

[4] शुक्ला, रानी (2010), बैंकिंग उद्योग एवं आर्थिक सुधार, इण्टरनेशलन रिफर्ड रिसर्च जर्नल, सितम्बर, 2010, वा0-2, इश्यू-20, पृ0 43-44

[5] धर, प्रांजल (2010), बैंकिंग क्षेत्र : विकास व चुनौतियां, योजना, फरवरी 2010.

[6] अरोड़ा, वेद प्रकाश (2010), सार्वजनिक बैंक वित्तीय जगत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, योजना, फरवरी 2010.